Ministry of Home Affairs-Major Achievements, significant Development and important events for the month of September, 2023.

Union Home Secretary taken following meetings during the month of September, 2023:

(i) On 01.09.2023, meeting with Chief Secretary of Manipur to review the security situation of the State of Manipur.
(ii) On 22.09. 2023, meeting with Chief Secretary of Tripura to review the progress of implementation of Bru Agreement (2020).
(iii) On 30.9.2023, meeting with the delegation of Eastern Nagaland People's Organization (ENPO) to discuss their demands.

2. Union Home Secretary chaired a meeting of Sub-Committee of National Executive Committee (SC-NEC) on 12.09.2023 to consider the Post Disaster Needs Assessment (PDNA) reports for recovery and reconstruction needs in respect of the States of Assam, Gujarat and Uttarakhand.

3. Union Home Secretary held a meeting on 22nd September, 2023 to consider the report of Inter-Ministerial Central Team (IMCT) on cyclonic storm 'Biparjoy" of 2023 in Gujarat.

4. A meeting was held with Members of NDMA on 27th September, 2023 to review progress of activities under the National Disaster Mitigation Fund.

5. Ceasefire Agreement with National Socialist Council of Nagaland (K) Niki group has been extended for a further period of one year w.e.f. 08.09.2023 to 07.09.2024.

6. 8 districts and 21 Police Station areas in 5 other districts of Nagaland and Tirap, Changlang and Longding districts of Arunachal Pradesh and area of 3 Police Stations in Namsai district of Arunachal Pradesh, bordering Assam have been declared as 'disturbed area' under Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 (AFSPA) for a period of six (6) months w.e.f. 01.10.2023 upto 31.3.2024 vide MHA's Notifications dated 26.9.2023.

7. Government of Manipur has declared the entire State of Manipur excluding the areas of 19 Police Stations as 'disturbed area' for a period of six (6) months w.e.f. 01.10.2023 vide Notification dated 27.09.2023.

8. In Assam, AFSPA has been removed from 4 more districts vide State of Assam's Notification dated 27.09.2023.

9. 31st meeting of the Northern Zonal Council was held on 26.09. 2023 in Amritsar.

10. NOC issued in respect of proposal of change in the name of

(i) Villages "Longpho" as "Longphaoh", "Longching" as "Longchang", "Goching" as "Chi Guhching", "Tang" as "Tangnyu", "Tingalibam" as "Sakho" in Mon district & village "Dimapur" as "Phuheto", in Dimapur district, Nagaland.
(ii) "Udhampur Railway Station" as "Martyr Captain Tushar Mahajan Railway Station" in Udhampur district, Jammu & Kashmir.

11. Meeting of High Powered Committee (HPC) was held on 04.09.2023 to consider the Action Plan proposals of the Financial year 2023-24 pertaining to Maharashtra, Lakshadweep, Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu under the Scheme of Assistance to States & UTs for Modernization of Police (ASUMP).

12. A meeting of Emergency Response Group was held on 01.09.2023 to review and discuss cyber security issues related to G20 Summit. In order to keep a close watch and to monitor any untoward incidents of cyber-attack, it was decided to establish a 24*7 Coordination Control Room comprising of I4C, CERT-In, NCIIPC, Delhi Police and NIC-CERT to manage cyber-attack during the G-20 leader Summit.

13. A meeting was held on 05.09.2023 to discuss the provisions of Secure e-mail set up developed by NIC for 10000 users of Critical/sensitive Ministry/Department/ Organization. A list of 17 Ministries /Departments was provided and discussed and agreed that in the initial phase 10000 users may be migrated to the secure ZTA e- mail set up by NIC. The same was followed by a review meeting which was held on 13.09.2023.

14. A series of one-day Review meeting-cum-workshop of regional Joint Cybercrime Coordination Team (JCCT) was organized and coordinated by I4C at Hyderabad on 15.09.2023 and at Gandhinagar on 25.09.2023 for meaningful review of JCCT and effective coordination with I4C to prevent cybercrime.

15. 1st Meeting of Committee constituted to study the best practices in the world on Transport Security was held on 20.09.2023 to discuss and find out an appropriate legal and operational framework for transport security in the country considering the national security perspectives and existing mechanisms.

16. An Empowered Committee Meeting for Financial Inclusion in LWE affected districts was held on 22.09.2023 under AS(LWE) with Officers of D/ o Financial Services and D/o Post.

17. 02 Advisories were issued to the State Governments/ CAPFs to sensitize them to counter the LWE activities in the LWE affected areas.

****

गृह मंत्रालय- सितंबर,2023 की प्रमुख उलब्धियाँ, उल्लेखनीय घटनाक्रम और महत्वपूर्ण कार्यक्रम।

सितंबर, 2023 के दौरान केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में निम्नलिखित बैठकें आयोजित की गई:

(i) दिनांक 01.09.2023, को मणिपुर राज्य की सुरक्षा की स्थिति की समीक्षा करने के लिए मणिपुर के मुख्य सचिव के साथ बैठक।
(ii) दिनांक 22.09.2023 को ब्रू करार (2020) के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करने के लिए त्रिपुरा के मुख्य सचिव के साथ बैठक।
(iii) दिनांक 30.09.2023 को ईस्टर्न नागालैंड पीपुल्स आर्गनाइजेशन (इएनपीओ) की माँगों पर विचार-विमर्श करने के लिए उनके साथ बैठक।

2. केंद्रीय गृह सचिव ने असम, गुजरात और उत्तराखंड राज्यों के संबंध में समुत्थान और पुनर्निर्माण की जरूरतों के लिए आपदा पश्चात आवश्यकता मूल्यांकन (पी डी एन ए) रिपोर्टों पर विचार करने के लिए दिनांक 12.09.2023 को राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की उप समिति की (एससी-एनईसी) बैठक की अध्यक्षता की।

3. केंद्रीय गृह सचिव ने गुजरात में वर्ष, 2023 के चक्रवाती तूफान 'बिपरजोय' पर अन्तर-मंत्रालयी केंद्रीय टीम (आईएमसीटी) की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए 22 सितंबर, 2023 को एक बैठक की।

4. दिनांक 27.09.2023 को राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष के तहत गतिविधियों की प्रगति की समीक्षा करने के लिए एनडीएमए के सदस्यों के साथ एक बैठक आयोजित की गई।

5. नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल आफ नागालैंड (के) निकी समूह के साथ युद्ध विराम को और एक वर्ष अर्थात दिनांक 08.09.2023 से दिनांक 07.09.2024 तक बढ़ा दिया गया है।

6. नागालैंड के 8 जिलों तथा 5 अन्य जिलों के 21 पुलिस स्टेशनों के तहत आने वाले क्षेत्रों तथा अरूणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग और लांगडिंग जिलों में तथा असम के सीमा से लगे अरूणाचल प्रदेश के नामसैद जिले के 3 पुलिस स्टेशनों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को गृह मंत्रालय के दिनांक 26.09.2023 की अधिसूचना के माध्यम से सशस्त्र बल (विशेष शक्तियाँ) अधिनियम, 1958 (आफस्पा) की धारा 3 के तहत दिनांक 01.10.2023 से 31.03.2024 तक (छ) माह के लिए 'अशांत क्षेत्र' घोषित किया गया है।

7. मणिपुर सरकार ने 19 पुलिस स्टेशनों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर पूरे मणिपुर राज्य को दिनांक 27.09.2023 की अधिसूचना के माध्यम से दिनांक 01.10.2023 से 'अशांत क्षेत्र' घोषित किया है।

8. असम में, दिनांक 27.09.2023 की असम राज्य की अधिसूचना के माध्यम से 4 और जिलों से आफस्पा हटा दिया गया है।

9. दिनांक 26.09.2023 को अमृतसर में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 31 वीं बैठक आयोजित की गई।

10. निम्नलिखित नामो के परिवर्तन के प्रस्ताव के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी किया गया।

(i) नागालैंड के मोन जिले में "लाँगफो" गाँव का "लाँगफाओह" "लाँगचिंग" गाँव का "लाँगचैंग", गोचिंग को चि गुहचिंग, "ताँग" गाँव का "ताँग्यू", "तिंगालिबम" गाँव का "साखो" तथा दीमापुर जिले में "दीमापुर" गाँव का "फुहेतो" के रूप में नाम परिवर्तित किया गया।

(ii) जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में "उधमपुर रेलवे स्टेशन" का नाम परिवर्तित करके "शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन" किया गया।

11. पुलिस आधुनिकीकरण के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता योजना (एएसयूएमपी) के तहत महाराष्ट्र, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव के संबंध में वित्तीय वर्ष 2023-24 के कार्य योजना के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए दिनांक 04.09.2023 को उच्चाधिकार प्राप्त समिति (एचपीसी) की बैठक आयोजित की गई।

12. जी 20 नेता शिखर वार्ता से जुड़े साइबर सुरक्षा मुद्दों की समीक्षा तथा विचार-विमर्श करने के लिए दिनांक 01.09.2023 को आपातकालीन कार्य समूह की बैठक आयोजित की गई। साइबर आक्रमण पर पैनी नजर रखने तथा किसी अप्रिय घटना की निगरानी करने के लिए आई4सी, सीईआरटी-इन, एनसीआई आईपीसी, दिल्ली पुलिस और एनआईसी-सीईआरटी को शामिल कर 24x7 समन्वय नियंत्रण कक्ष स्थापित करने का निर्णय लिया गया ताकि जी 20 नेता शिखर वार्ता के दौरान साइबर आक्रमण का प्रबंधन किया जा सके।

13. संवेदनशील/अतिसंवेदनशील मंत्रालय/विभाग/संगठन के लिए 10000 प्रयोगकर्ताओं के लिए एनआईसी द्वारा विकसित सेक्युरी-मेल व्यवस्था के प्रावधानों पर चर्चा करने के लिए दिनांक 05.09.2023 को एक बैठक आयोजित की गई। 17 मंत्रालयों/विभागों की सूची प्रदान की गई, चर्चा की गई और सहमति बनी कि आरंभिक चरण में 10000 प्रयोगकर्ताओं को एनआईसी द्वारा स्थापित सुरक्षित जेटीए ईमेल में हस्तांतरित किया जाए। इसके उपरांत दिनांक 13.09.2023 को एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

14. साइबर अपराध रोकने के लिए जेसीसीटी की सार्थक समीक्षा तथा आई4सी के साथ कारगर समन्वय करने के लिए दिनांक 15.09.2023 को हैदराबाद और दिनांक 25.09.2023 को गाँधी नगर में आई4सी द्वारा क्षेत्रीय संयुक्त साइबर अपराध समन्वय टीम (जेसीसीटी) की अनेक एक दिवसीय समीक्षा बैठक-सह कार्यशाला का आयोजन और समन्वय किया गया।

15. राष्ट्रीय सुरक्षा परिप्रेक्ष्यों और मौजूदा तंत्रों पर विचार कर देश में परिवहन सुरक्षा के लिए उपयुक्त विधिक और प्रचालनात्मक ढाँचे पर विचार कर समाधान प्राप्त करने के लिए साइबर सुरक्षा जगत में सर्वोत्तम प्रथाओं का अध्ययन करने के लिए गठित समिति की पहली बैठक आयोजित की गई।

16. एएस (एलडब्ल्यूई) के तहत एलडब्ल्यूई प्रभावित जिलों में वित्तीय समावेशन के लिए दिनांक 22.09.2023 को वित्तीय सेवाएं विभाग और डाक विभाग के अधिकारियों के साथ अधिकार प्राप्त समिति की बैठक आयोजित की गई ।

17. एलडब्ल्यूई प्रभावित क्षेत्रों में (एलडब्ल्यूई) गतिविधियों का मुकाबला करने के तौर-तरीके से राज्य सरकारों /केंद्रीय सशस्त्र सुरक्षा बलों को अवगत कराने हेतु उन्हें एडवाइज़री जारी की गईं।

****